मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट-2026 में आमंत्रित कंपनियों के प्रतिनिधिमंडलों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने निवेशकों से आव्हान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में राजस्थान आएं, यहां निवेश की अपार संभावनाएं हैं।

हम राजस्थान को तकनीक व नवाचार का ग्लोबल लीडर बनायेंगे- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने डिजिफेस्ट में आमंत्रित कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया

जयपुर, 4 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों की आवश्यकताओं और सुविधाओं को केंद्र में रखते हुए नीतियों का निर्माण कर रही है। इसी कड़ी में राजस्थान ग्लोबल कैपबिलिटी सेंटर पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी जैसी प्रमुख नीतियां लाई गई हैं। ये नीतियां राजस्थान को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में हब बनाएगी।

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निवेशकों के साथ निरंतर संपर्क स्थापित करके उनके सुझावों और आवश्यकताओं पर त्वरित कार्यवाही करें।

शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट-2026 में आमंत्रित कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 8 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग निवेशकों का राजस्थान में विश्वास का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री ने निवेशकों से आव्हान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में राजस्थान आएं, राज्य सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर राजस्थान को तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निवेशकों के साथ निरंतर संपर्क स्थापित करते हुए उनके सुझाव और आवश्यकताओं पर त्वरित कार्य करने के निर्देश भी दिए।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि प्रदेश में अनुकूल औद्योगिक वातावरण का निर्माण हो रहा है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, राजस्थान डेटा सेंटर, राजस्थान एआई एमएल नीतियों के साथ 7 हजार से अधिक आई स्टार्टअप्स का तंत्र प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का मजबूत नेटवर्क स्थापित कर रहा है।

कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिकल साइंस, ग्रीन इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप्स, मेन्युफैक्चरिंग, डेटा, स्किल डवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स आदि क्षेत्रों के संबंध में सुझाव दिए।

अप्रेल में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी- अमित शाह

पुदुक्कोट्टई(तमिलनाडु), 04 जनवरी। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर हैं, उन्होंने रविवार को पुदुक्कोट्टई में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु के अंदर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आने वाले चुनावों में, भाजपा, एआईएडीएमके और हमारी सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर कांग्रेस और डीएमके को आखिरी टक्कर देने के लिए एक मजबूत गठबंधन बनाने जा रही है। डीएमके सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है।

■ केन्द्रीय गृह मंत्री ने रविवार को एक जनसभा में यह दावा किया।

लाखेरी में श्रद्धालुओं पर ट्रक पलटा, तीन की मौत

तेज रफ्तार से चल रहा ट्रक सड़क पर बने गहरे गड्ढों से असंतुलित होकर श्रद्धालुओं पर गिरा

कोटा, (निसं)। जिला बूंदी के लाखेरी उपखंड क्षेत्र में रविवार को देईखेड़ा थाना इलाके में पापड़ी रेलवे ओवरब्रिज के समीप कपास से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर माताजी के दर्शन करने जा रहे पैदल श्रद्धालुओं पर पलट गया। हादसे में तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब आठ घायल हो गये।

जानकारी के अनुसार कोटा की ओर से तेज रफ्तार में आ रहा कपास से भरा ट्रक पापड़ी ओवरब्रिज के पास पहुंचते ही सड़क पर बने गहरे गड्ढों के कारण अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, और सड़क किनारे पैदल चल रहे श्रद्धालु इसके नीचे दब गए। घटना की सूचना मिलते ही देईखेड़ा और लाखेरी थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कराया। ट्रक के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए क्रेन की सहायता से पलटे ट्रक को सीधा किया गया। एम्बुलेंसों की मदद से घायलों को नजदीकी लाखेरी अस्पताल पहुंचाया गया, बाद में घायलों को कोटा एमबीएस अस्पताल के लिये रैफर कर भर्ती करवाया गया।

■ हादसे की सूचना मिलने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला घायलों से मिलने अस्पताल पहुँचे। उन्होंने कोटा रेंज आईजी को घटना की जाँच करने के निर्देश दिए।

हादसे की सूचना मिलते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला घायलों से मिलने के लिये अस्पताल पहुंचे और घायलों की कुशलक्षेम पूछी। ओम बिरला ने घटना को दुखद बताया और कोटा रेंज आईजी राजेन्द्र गोयल को पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिये।

जानकारी के अनुसार दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों की भीड़ ने ट्रक पर फैली कपास को आग लगा दी, इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और भीड़ ने बाद में ट्रक को ही आग के हवाले कर दिया। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस ने समझाईश की और दमकल बुलाकर ट्रक में लगी आग को बुझाया।

राज्य चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की ''निर्विरोध'' जीत की जाँच के आदेश दिए

विपक्षी दलों का आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी ने करोड़ों रूपए का लालच और धमकी देकर नामांकन वापस कराए

मुंबई, 04 जनवरी। महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों से पहले बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिवसेना (शिंदे गुट) के उम्मीदवारों का ''निर्विरोध'' चुना जाना विवादों में घिर गया है क्योंकि विपक्षी पार्टियां इस प्रक्रिया को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रही हैं।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेताओं ने संकेत दिया है कि राज्य चुनाव आयोग की जांच के साथ-साथ निर्विरोध चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी योजना बनाई जा रही है। महाराष्ट्र के विभिन्न नगर निगमों में 67 उम्मीदवार बिना मुकाबले के चुने गए हैं। इनमें से अधिकतर उम्मीदवार भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) के हैं। गौरतलब है कि मालेगांव से इस्लाम पार्टी के एक उम्मीदवार को भी बिना मुकाबले के चुना गया है। विपक्षी पार्टियों ने इनकी कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि सत्ताधारी पार्टियों ने करोड़ों रुपये का लालच और डरा-धमकाकर विरोधी उम्मीदवारों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया। राज्य चुनाव आयोग ने इन आरोपों को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी चुनावों की जांच के आदेश दिए हैं।

■ महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के नेता कह रहे हैं कि राज्य चुनाव आयोग की जाँच के साथ ही निर्विरोध चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ कानूनी कार्यवाही पर भी विचार किया जा रहा है।

मेयर ममदानी ने अमेरिकी अभियान को युद्ध की कार्यवाही बताया

न्यूयॉर्क, 04 जनवरी। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने वेनेज़ुएला के खिलाफ चलाए गए अमेरिकी अभियान, एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व, को युद्ध की कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय व संघीय कानून का उल्लंघन बताया है। ममदानी ने कहा कि सत्ता परिवर्तन की यह खुलेआम कोशिश न केवल विदेशों में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को प्रभावित करती है, बल्कि इसका सीधा असर न्यूयॉर्क निवासियों पर भी पड़ता है, जिनमें वेनेज़ुएला के हजारों नागरिक भी शामिल हैं । मेयर ने वेनेज़ुएला के नागरिकों और हर न्यूयॉर्क वासी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते कहा कि उनका प्रशासन स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा और इससे संबंधित दिशा-निर्देश जारी करेगा। ममदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ''एक संप्रभु राष्ट्र पर एकतरफा हमला करना युद्ध की कार्रवाई और संघीय व अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है।''

गौरतलब है कि मादुरो को न्यूयॉर्क शहर के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर (एमडीसी) में भेजा गया है। यह सेंटर अपनी खराब स्थितियों के कारण घिनौना और भयानक बताया जाता है।

भारत ने वेनेज़ुएला में शांति व स्थिरता बनाए रखने का आव्हान किया

विदेश मंत्रालय ने वेनेज़ुएला में मौजूद भारतीयों को स्थानीय यात्रा सीमित करने का आग्रह किया

नयी दिल्ली, 04 जनवरी। भारत ने रविवार को वेनेज़ुएला में हालिया घटनाक्रम पर गहरी चिंता जतायी है और कहा कि वह दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में बदलती सुरक्षा स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर वेनेज़ुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी और सभी संबंधित पक्षों से बातचीत के जरिये संकट का शांतिपूर्ण समाधान निकालने, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाये रखने का आ ान किया। बयान में यह भी कहा गया है कि काराकस में भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के संपर्क में है और इस अशांत अवधि के दौरान उन्हें सभी जरूरी मदद जारी रखी जायेगी। इससे पहले शनिवार को विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को वेनेज़ुएला की सभी गैर-जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी थी। सलाह में, वेनेज़ुएला में मौजूद भारतीयों से सतर्क रहने, सार्वजनिक सभाओं से बचने, घर के अंदर रहने और सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय यात्रा सीमित करने का आग्रह किया गया है। यह एडवाइज़री वेनेज़ुएला की सुरक्षा स्थिति में नाटकीय बदलाव के कारण जारी की गयी है, जो काराकस में फोर्ट ट्ययूना सैन्य परिसर समेत प्रमुख सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमले से पैदा हुई है। विदेश मंत्रालय ने वेनेज़ुएला में भारतीय नागरिकों के लिए विशेष संपर्क विवरण प्रदान किये हैं। इसमें एक आपातकालीन हॉटलाइन और दूतावास ईमेल शामिल हैं।

■ काराकस में भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के संपर्क में है तथा अशांति के इस समय में उन्हें सभी जरुरी मदद करने के लिए तैयार है।

ममदानी के उमर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दिया, जिसमें भारत का नाम लेकर कथित तौर पर मुस्लिम समुदायों पर कार्रवाई का उल्लेख किया गया है। भाजपा के एक और प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि "अगर भारत की संप्रभुता को चुनौती दी गई, तो 140 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट खड़े होंगे।"

भाजपा नेताओं की उग्र राष्ट्रवादी भाषा के बावजूद, ममदानी का नोट और अमेरिकी सांसदों के बयान इस मुद्दे को लेकर भारत पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा सकते हैं।

उमर ख़ालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर पर 2020 के दिल्ली दंगों की एक "बड़ी साजिश" रचने के केस में कठोर यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अब तक उनका मुकदमा शुरू नहीं हुआ है और उन पर लगे आरोप भी अभी तक साबित नहीं हो पाए हैं।

ममता बनर्जी ने एसआईआर पर फिर चुनाव आयोग को पत्र लिखा

कोलकाता, 04 जनवरी। पश्चिम बंगाल कीमुख्यमंत्री ममता बनर्जी नेविशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकरएक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है। सीएम ममता ने अपने पत्र में बंगाल में एसआईआर के दौरान कथित अनियमितताओं, प्रक्रियात्मक उल्लंघनों और प्रशासनिक खामियों पर चिंता जताई। सीईसी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया से समझौता हुआ है, यह हमारे लोकतंत्र के मूल ढ ांचे और संविधान की भावना पर हमला है। अपने पत्र में ममता बनर्जी ने मांग करते हुए कहा कि मैं आपसे आग्रह करती हूं कि एसआईआर की इन खामियों को तुरंत ठीक करें या इस मनमानी, अनियोजित प्रक्रिया को रोकें। अगर इसे अपने वर्तमान स्वरूप में जारी रहने दिया गया, तो एसआईआर से बहुत ज्यादा नुकसान होगा।

■ उन्होंने कहा कि खामियों को दूर करें या मनमानी, अनियोजित प्रक्रिया रोकें।

अमेरिका के 100 शहरों में, वेनेज़ुएला पर सैन्य कार्यवाही के विरोध में प्रदर्शन

प्रदर्शनकारियों ने "वेनेज़ुएला की रक्षा करो, मादुरो को आज़ाद करो" के नारे लगाए

न्यूयॉर्क, 04 जनवरी। वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने वाली अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के विरोध में रविवार को सैकड़ों लोग मैनहट्टन की सड़कों पर उतरे।

यह मार्च वाशिंगटन, बॉस्टन, लॉस एंजलिस, अटलांटा, शिकागो और मायामी जैसे 100 से अधिक अमेरिकी शहरों में होने वाले "वेनेज़ुएला पर कोई युद्ध नहीं" प्रदर्शनों का हिस्सा था।

न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों के हाथों में, वेनेज़ुएला से हाथ हटाओ, कैरिबियन से अमेरिका बाहर निकले, वेनेज़ुएला के तेल के लिए कोई युद्ध नहीं, और अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ वेनेज़ुएला की रक्षा करो, लिखे हुए पोस्टर थे। भीड़ में "वेनेज़ुएला की रक्षा करो, मादुरो को आजाद करो" के नारे भी गूंज रहे थे।

मार्च में शामिल न्यूयॉर्क के निवासी कैरन ने कहा, "यह युद्ध मादक पदार्थों के बारे में नहीं है, यह वेनेज़ुएला के तेल के बारे में है। आपको वेनेज़ुएला में कदम रखने और वहां हमला करने का अधिकार कैसे है? ऐसा महसूस होता है जैसे हम अपराधियों की तरह काम कर रहे हैं। हम यहां यह कहने आए हैं कि यह एक अन्यायपूर्ण कार्रवाई है।"

■ युद्ध विरोध समूह ने कहा कि अमेरिकी युद्ध वेनेज़ुएला के लोगों की मौत व विनाश का कारण बनेगा। यह युद्ध अमेरिकी नागरिकों के टैक्स के पैसों को अकल्पनीय मात्रा में खा जाएगा।

पाकिस्तान के एक कॉलेज छात्र हसन ने कहा कि विदेशों में अमेरिका के नेतृत्व में सरकार बदलने के प्रयास नए नहीं हैं, लेकिन कम से कम पहले यह नकाब पहनकर किया जाता था, जैसे मध्य पूर्व में लोकतंत्र बहाल करने के नाम पर। उन्होंने कहा कि लेकिन, आज इसने नकाब उतार दिया है। यह कार्रवाई काफी स्पष्ट रूप से तेल और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में है।

टाइम्स स्क्वायर रैली में एक वक्ता ने कहा कि वेनेज़ुएला के लोग अपने देश को चलाने वाले या अपने तेल, गैस, सोने या किसी भी संसाधन को चुराने वाले अमेरिका को स्वीकार नहीं करेंगे। वहां कड़ा प्रतिरोध होगा। वह युग अब खत्म हो गया है।

आयोजकों में से एक, आंसर कोअलिशन ने काराकास पर हालिया अमेरिकी बमबारी और मादुरो को पकड़े जाने की निंदा की। उन्होंने अमेरिकियों से एक और अंतहीन युद्ध को नकारने का आ ान किया।

इस युद्ध-विरोधी समूह ने एक बयान में कहा, "अमेरिकी युद्ध वेनेज़ुएला के लोगों के लिए मौत और विनाश का कारण बनेगा। युद्ध हमारे टैक्स के पैसों की अकल्पनीय मात्रा को खा जाता है, जबकि कामकाजी परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं। लोगों को सड़कों पर उतरने और वेनेज़ुएला पर ट्रंप के युद्ध को ना कहने की जरूरत है!"

कांग्रेस व इंडिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि विपक्षी दलों में अपनी संस्थाओं के प्रति सम्मान, आंतरिक संवाद में ईमानदारी और रणनीतिक दृष्टि से विनम्रता नहीं होगी तो यह जड़ता की ओर बढ़ सकती है तथा इसमें नया विकास नहीं होगा। इंडिया ब्लॉक, और खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आज मुद्दों की कमी से पीड़ित नहीं, बल्कि विरोधाभासों की भरमार से उलझी हुई है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों और लगातार विधानसभा चुनावों में हार के बाद, विपक्ष एक सही मायने में चौराहे पर खड़ा है। फिर भी, रणनीति फिर से तय करने या मतदाताओं की भावनाओं से जुड़ने के बजाय, ऐसा लगता है कि यह उन मुद्दों पर और ज़्यादा ज़ोर देने के लिए दृढ़ है, जिन्हें मतदाता पहले ही खारिज कर चुके हैं। इसका नतीजा विरोध नहीं, बल्कि भटकाव है, बदलाव नहीं, बल्कि दोहराव है। ज़मीनी हकीकत से यह अलगाव अब साफ दिख रहा है। नए वर्ष 2026 में प्रवेश कर रही कांग्रेस एक विश्वसनीय विकल्प बनने के बजाय, भाजपा को निशाना बनाने वाली ताकत के रूप में बनी हुई है और इससे उसकी अभी जितनी सीटें हैं उनमें बढ़ोतरी की संभावना खत्म हो सकती है। हो सकता है कि वह मामूली सी बढ़त के साथ 95-98 सीटों तक पहुंच सकती है, लेकिन यह एक ऊपरी सुधार है, जो एक गहरी रणनीतिक विफलता को छिपाता है। हालांकि, विपक्ष के लिये, भूगोल से ज़्यादा नुकसानदायक विचारधारा है। जब सनातन धर्म का मज़ाक उड़ाया जाता है, उसका कार्टून बनाया जाता है या उस पर हमला किया जाता है, तो विपक्षी खेमा साफ तौर पर चुप रहता है, लेकिन जब उमर खालिद जैसे लोगों की बात होती है, जो 2020 से दिल्ली दंगों की साज़िश के मामले में जेल में पड़े हैं, तो विपक्ष तुरंत गुस्सा जाहिर करता है। यह चयनात्मक नैतिकता इस धारणा को मज़बूत करती है कि कांग्रेस अब एक सुसंगत विश्वदृष्टि से नहीं, बल्कि वैचारिक सुविधा और एक्टिविस्ट फैशन से निर्देशित हो रही है।

जैसलमेर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तहसील का रहने वाला है। एटीएस पिछले कई दिनों से मौलवी पर नजर बनाए हुई थी। शनिवार देर शाम जयपुर से आई एटीएस की टीम ने कुरिया बेरी गांव में संदिग्ध को घेरा और उसे अपने साथ ले गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए संदिग्ध को सीधे जयपुर ले जाया गया है। किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज और तनोटमाता मंदिर के निकटवर्ती क्षेत्रों में इस तरह की संदिग्ध गतिविधियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक मानी जा रही हैं।

अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय फायनैंशियल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रिस्क बहुत ज्यादा है। भारत में क्रेडिट चक्र अक्सर अति-उत्साह और फिर सख़्ती के बीच झूलते रहे हैं, जिससे बैंकों और कंपनियों पर बोझ बढ़ा है। मज़बूत जाँच-प्रणाली (स्ट्राँग अण्डरराइटिंग) और गहरे पूँजी बाज़ार की गैरमौजूदगी में, तेज़ ऋण वृद्धि, टिकाऊ खपत और निवेश को सपोर्ट करने के बजाय, एसैट की कीमतों को बढ़ा सकती है। वहीं, कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार अब भी कम लिक्विडिटी, नियमों की बिखरी व्यवस्था और सीमित निवेशकों की वजह से कमज़ोर है, इसलिए इसके द्वारा तुरंत बड़े बदलाव होने की उम्मीद पर संदेह बना रहता है।

उद्यमिता (एन्टरप्रैन्योरशिप) और स्टार्ट-अप में तेजी भी इस आशावादी कहानी का केन्द्र हैं। जबकि प्राइवेट कैपिटल इन्फ्लो और डिजिटल तकनीक अपनाने से नए व्यवसाय ज़रूर बढ़े हैं, पर इनका बड़ा हिस्सा उपभोक्ता-केन्द्रित, प्लेटफ़ॉर्म-आधारित मॉडलों में है, जहाँ रोज़गार सृजन कम और मुनाफ़ा अनिश्चित है। वैश्विक नक़दी सख़्त होने से यह साफ़ हो गया है कि यह इकोसिस्टम बाहरी पूँजी पर कितना निर्भर है। जब तक इनोवेशन तेजी से डीप-टैक्नॉलजी, एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग और अनुसंधान-आधारित क्षेत्रों की ओर नहीं मुड़ेगा, तब तक यह वृद्धि टिकाऊ नहीं बन पाएगी।

■ अगर, भारत का आई.टी. सैक्टर इस तब्दीली को नहीं पहचान पाया और इसके अनुरुप अपने आप को नहीं ढाल पाया तो आई.टी. सैक्टर की पुरानी सफलता को दोहरा पायेगा, यह विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

■ इसी प्रकार यह भी माना जाता है, और काफी ढिंढोरा पीटा जाता है कि भारत में डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत हो गया है। यह सच है, पर, यह डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, जैसे यू.पी.आई. के कारण ट्रांजेक्शन खर्च कम हुआ है, पारदर्शिता बढ़ी है तथा इकोसिस्टम एक्टिविटी का फॉर्मलाइज़ेशन तेज हुआ है तथा इस डिजिटल कार्यकुशलता से कंज़म्शन बढ़ा है, पर, बड़े स्केल पर औद्योगिक क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी है। ऐसा ही जोखिम भारत की बहुचर्चित युवा लेबर फोर्स व स्टार्टअप्स के बारे में भी है।

जनसांख्यिकी (डैमोग्राफिक्स), जिसे अक्सर भारत की सबसे स्थायी ताक़त बताया जाता है, एक ज्यादा मुश्किल तस्वीर भी पेश करती है। युवा और बढ़ता वर्कफोर्स तभी लाभ दे सकता है, जब अर्थव्यवस्था पर्याप्त उत्पादक रोज़गार पैदा करे। महिलाओं की सीमित श्रम-भागीदारी, बड़े पैमाने पर अण्डर एम्प्लॉयमैंट और कौशल की कमी इस बात का ख़तरा बढ़ाते हैं कि जनसांख्यिकीय लाभ बोझ में बदल जाए। प्रति व्यक्ति आय भले ही बढ़े, पर बढ़ती असमानता उपभोग में उछाल को सीमित कर सकती है।

सप्लाई साइड पर, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी मैनुफैक्चरिंग केपबिलिटी बनाना अभी भी एक स्ट्रैटेजिक लक्ष्य है, पक्का नतीजा नहीं है। नीतिगत प्रयासों और प्रोत्साहन योजनाओं के बावजूद, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में भारत की हिस्सेदारी पूर्वी एशिया के देशों की तुलना में कम है। जटिल और हाई वैल्यू इण्डस्ट्रीज़ में सफलता के लिए पैमाना, स्थिर नियम और तकनीकी गहराई चाहिए, जहाँ प्रगति एक जैसी नहीं रही है। साथ ही, बढ़ते अनुपालन (कम्प्लायंस) बोझ और गुणवत्ता नियंत्रण के नियम संरक्षणवाद की ओर झुकाव बढ़ा सकते हैं, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धा कमज़ोर पड़ सकती है।

उत्पादकता के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमैंट, खासकर लॉजिस्टिक कॉस्ट को तेजी से कम करने की महत्वाकांक्षा को जरूरी फैक्टर के रूप में सही पहचाना गया है। लेकिन भूमि अधिग्रहण की चुनौतियाँ, वित्तीय सीमाएँ और राज्यों में प्रशासनिक अड़चनें काम की रफ़्तार धीमी कर सकती हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़े बिना भारी सरकारी निवेश सरकारी खजाने पर जोर डाल सकता है, जिससे लगातार इन्फ्रास्ट्रक्चर आधारित विकास की गुंजाइश सीमित हो जाएगी।

कुल मिलाकर देखें तो भारत की दीर्घकालिक विकास-कहानी को अवश्यंभावी उन्नति के बजाय, शर्तों पर टिकी यात्रा समझना बेहतर है। तेज़ विस्तार के लिए आधार मौजूद है, पर इसकी सफलता लेबर मार्केट, शिक्षा, वित्त और औद्योगिक नीति में गहरे सुधारों पर निर्भर करेगी। इनके बिना भारत शायद कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से तेज बढ़ेगा, लेकिन वो ऐतिहासिक छलांग नहीं लगा पाएगा, अत्यधिक आशावादी अनुमान जिसकी बात करते हैं।

दिल्ली में रविवार सुबह वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में

नयी दिल्ली, 04 जनवरी। दिल्ली के कई इलाकों में रविवार सुबह वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई जबकि तेज हवाएं चलती रहीं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीबीसीबी) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आज सुबह नौ बजे तक कई निगरानी केंद्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का स्तर बहुत खराब बना रहा। 301 से 400 के बीच का एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में आता है और इससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।

तेज हवाएं चलने के बावजूद राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है। सुबह में हवाओं से प्रदूषण में थोड़ी कमी आई लेकिन यह कमी एक्यूआई को मध्यम स्तर तक लाने में मददगार साबित नहीं हुई।

डेरा प्रमुख राम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इससे पहले 5 अगस्त, 2025 को उसके जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए इसी तरह की 40 दिन की पैरोल दी गई थी। अगस्त 2017 में बलात्कार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से यह 15वीं बार होगा जब राम रहीम को पैरोल या फरलो पर जेल से रिहा किया जाएगा। गौरतलब है कि राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के लिए उम्रकैद की सजा भी सुनाई गई है।

उसे एक अक्टूबर, 2024 को हरियाणा विधानसभा चुनावों से कुछ दिन पहले 20 दिन की पैरोल और अगस्त 2024 में 21 दिन की फरलो दी गई थी। उसे फरवरी 2022 में पंजाब विधानसभा चुनावों से कुछ समय पहले तीन सप्ताह की फरलो दी गई थी। राम रहीम इन रिहाई के दौरान कई मौकों पर उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में डेरा सच्चा सौदा आश्रम में रुका है।

प्रियंका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वर्ष होने वाले असम के विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। असम में पिछले दस वर्षों से भाजपा सरकार में है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908